

(घ) उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित कारणों की वजह से कम क्षमता उपयोग के परिणाम स्वरूप हानियां हुईं। इस एकक को नियमित और पर्याप्त पावर की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। संयंत्र के नाजुक उपकरणों की सुरक्षा के लिये सरकार ने एक गैस टर्बाइन के अतिरिक्त रक्षित विद्युत प्रजनन संयंत्र की भी अनुमति दी है। निरन्तर कठिनाई उत्पन्न करने वाले कुछ उपकरणों के प्रतिस्थापन/परिवर्धन द्वारा संयंत्र के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिये विभिन्न उपाय भी किये जा रहे हैं।

बिहार में बेगूसराय, पूर्णिया और मुंगेर में दूरदर्शन केन्द्रों के लिए "सेटेलाइट रिसेप्टर्स" की स्थापना

2299. श्रीमती कृष्णा साही: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन राज्यों के नाम क्या हैं जहाँ सरकार का विचार दूरदर्शन केन्द्रों के लिए "सेटेलाइट रिसेप्टर्स" की स्थापना करने का है ;

(ख) बिहार के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ सरकार का विचार दूरदर्शन केन्द्रों के लिए इन "सेटेलाइट रिसेप्टर्स" की स्थापना का है और क्या बेगूसराय, पूर्णिया और मुंगेर को इस योजना में शामिल किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) "टी० वी० रिसेप्टर ओनली टरमिनलज" कहे जाने वाले उपग्रह रिसेप्टरों को छठी योजना अवधि के अन्त तक सभी राज्यों में लगाया जायेगा।

दूसरी किस्म के उपग्रह रिसेप्टरों, जिन्हें सीधे संग्रहण दूरदर्शन सैट कहा जाता है, को सामुदायिक अवलोकन के लिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के तीन-तीन जिलों के चुनिंदा विद्युतिकृत गावों में लगाने का प्रस्ताव है।

(ख) चालू योजना अवधि के अन्त तक इन्सैट-1 बी से कार्यक्रमों को रिले करने के लिए पटना और रांची में दो उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा दरभंगा, जमशेदपुर, गया, भागलपुर, धनबाद, मुंगेर, पुर्णिया और बेतिया में 8 अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को "टी० वी० रिसेप्टर ओनली टरमिनलज" के साथ लगाने का प्रस्ताव है।

बेगूसराय को दूरदर्शन सेवा पटना के प्रस्तावित उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर से प्राप्त होगी।

सीधे संग्रहण सैट कहे जाने वाले 300 उपग्रहण रिसेप्टरों को सामुदायिक अवलोकन के लिए रांची दूरदर्शन ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र से बाहर पलामाऊ, सिधभूमि और रांची के जिलों में लगाने प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Cost Economy for Setting up of Gas-based Fertiliser Plants

2300. SHRI A. T. PATIL : Will the Minister of CHEMICALS AND